(iv) Demand for a Central School at Ghazipur, U.P.

श्री जैनुल बशर(गाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट ओपीयम एण्ड अलकालेण्ड वर्क्स, गाजीपुर उत्तर प्रदेश ने एक केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव भेजा है। यह प्रतिष्ठान केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने से सम्बन्धित सभी शर्तों को पूरा करने को तैयार है।

गाजीपुर में अच्छी संख्या में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हैं। इनके अतिरिक्त सशस्त्र सेनाओं में केन्द्रीय पुलिस बलों तथा अन्य केन्द्र सरकार की सेवाओं में गाजीपुर जिले के लोग बड़ी संख्या में काम करते हैं। सशस्त्र सेनाओं और पुलिस बलों में काम करने वाले लोगों की तैनाती बहुधा ऐसे स्थानों पर होती है जहां पर अपना परिवार नहीं रख सकते। अधिकतर ऐसा भी होता है कि कभी वे परिवार रख पाते हैं और कभी अपने घरों को वापस भेज देते हैं। ऐसी स्थिति में उनके पुत्रों-पुत्रियों की शिक्षा में बाधा पड़ती है। ऐसी स्थिति में केन्द्रीय विद्यालय खुल जाने से ऐसे सरकारी कर्मचारियों तथा स्थानीय सरकारी कर्मचारियों को बहुत सुविधा हो जाएगी।

शिक्षा मंत्रालय से मेरा निवेदन है कि अगले सत्र से गाजीपुर में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की वह स्वीकृति प्रदान कर दे तथा इसकी पूरी व्यवस्था करे।

(v) Need to reorganise Trade Unions in Indian Railways

SHRI ERA AMBARASU (Chengalpattu) : There are two Federations in Railways *viz.* NFIR, affiliated to INTUC and AIRF, controlled by the Socialist Party. These are only federal bodies of recognized zonal railway unions.

The zonal unions are recognised unions and with this recognition, the office-bearers continue to hold the Unions in their control. They manipulate the membership and submit to Trade Union Registrar periodically to safeguard their registration. Some station masters, loco running staff etc. have formed category-wise unions. These unrecognised unions are also having more membership than recognised unions.

Those leaders of recognised federations and unions nominate their representatives from staff benefit fund committee to the Departmental and National Council level, without getting mandate of railwaymen. The zonal railway administration are not exercising any check, but simply accept lists of office-bearers without any verification of the credentials of the nominee. Hence, a high level committee should be formed to conduct elections at all levels in the trade unions in Indian Railways.

I urge upon the Minister to reorganise these unions by fair elections, which will bring one union for one industry to constitute a monitoring body, consisting of railway trade union leaders, railway officers, officials from the Labour Ministry and Consultative Committee Members of the Railway Ministry to conduct the elections.

(vi) Industrialisation of Jaunpur, U.P.

डा० ए० यू० आजमी (जौनपुर) : मिस्टर डिप्टी स्पीकर सर, इससे पहले दो दफा पार्लियामेंट में अपनी कान्सटीटुयेन्सी जौनपुर के पिछड़ेपन और बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार से मतालबा कर चुका हूं कि एक बड़ी इंडस्ट्री जौनपुर में लगाई जाए और सन् 1983 में यूनियन इंडस्ट्री मिनिस्टर ने अपने एक अखबारी बयान में कहा भी था कि जौनपुर के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए एक बड़ी इंडस्ट्री जौनपुर में लगाई जाएगी, जिससे मुझे और जौनपुर के तमाम लोगों को बड़ी मसर्रत हुई थी लेकिन 36 साल जिस तरह हमें सिर्फ वायदे ही वायदे मिलते रहे, वह ऐलान भी उन्हीं वायदों की फेहरिस्त में गुम हो गया।

जौनपुर में एक बड़ी इंडस्ट्री लगाने से जौनपुर का पिछड़ापन तो दूर होगा ही, साथ ही साथ बेरोजगारी की वजह से जो नौजवान तबका मुजरीमाना जिन्दगी गुजारने पर मजबूर होता है